विदेशी पूंजी एवं आर्थिक विकास
FOREIGN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH

आज आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है जो कि बाह्य सहायता से ही संभव होता है। अर्द्धविकसित देशों की यह समस्या होती है कि वहां पर्याप्त मात्रा में बचत नहीं होती है जिससे पूंजी निर्माण दर कम रहता है। अतः विदेशी पूंजी को निमंत्रण द्वारा उनके दोषों को दूर करके उसे आर्थिक विकास में सहायक बनाया जा सकता है।

विदेशी पूंजी दो तरह के होते हैं —

(a) निजी विदेशी पूंजी - इसके अन्तर्गत विदेशी पूंजीपतियों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विनियोग को शामिल किया जाता है

(b) सार्वजनिक विदेशी पूंजी - सार्वजनिक विदेशी पूंजी तीन प्रकार के होते हैं —

1. द्विपक्षीय महंगी विदेशी ऋण bilateral (Hard loan) - ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार को अंग्रेजी मुद्रा में ऋण देना
2. द्विपक्षीय सस्ती विदेशी ऋण (Soft loan) - USA द्वारा भारत को P.L 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न देना
   ☒ P.L 480 - स्थानीय करेंसी में भुगतान
3. बहुपक्षीय विदेशी सार्वजनिक ऋण Multilateral loan > IBRD, IFC, IDA, द्वारा उपलब्ध करें

~~विदेशी सार्वजनिक ऋण के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से पूंजी की प्राप्ति होती है जैसे IBRD, IMF IFC आदि।~~

आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी निम्नलिखित भूमिका अदा करती है।

1. प्रारंभिक जोखिम उठाने के लिए — विकास की प्रारंभिक अवस्था में जोखिम की संभावनाएं काफी अधिक होती है। अर्द्धविकसित देश में जोखिम उठाने वाले उद्यमियों का अभाव होता है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में जोखिम विदेशी पूंजीपति द्वारा उठाया जाता है जो बाद में देशी पूंजीपतियों द्वारा वसूल किया जाता है जिससे आर्थिक विकास होती है।

2. उद्योगों के निर्माण हेतु — आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। उद्योगों के निर्माण के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है जो कि विदेशी सहायता से ही संभव होता है।

3. तकनीकी विकास हेतु — विदेशी पूंजीपति जब कहीं भी पूंजी विनियोग करते हैं तब वे अपने साथ नये नये तकनीकी लाते हैं जो कि आर्थिक विकास में सहायक होता है।

☒ (कृषि अतिरिक्त स्थानीय करेंसी में भुगतान करने पर विक्रय गया)

जैसे पूंजी से उच्च तकनीकी विकास की अवस्थाओं को प्राप्त किया जाता है जैसा कि निचे के चित्र से स्पष्ट है—

"तकनीकी विकास की अवस्थाएं"

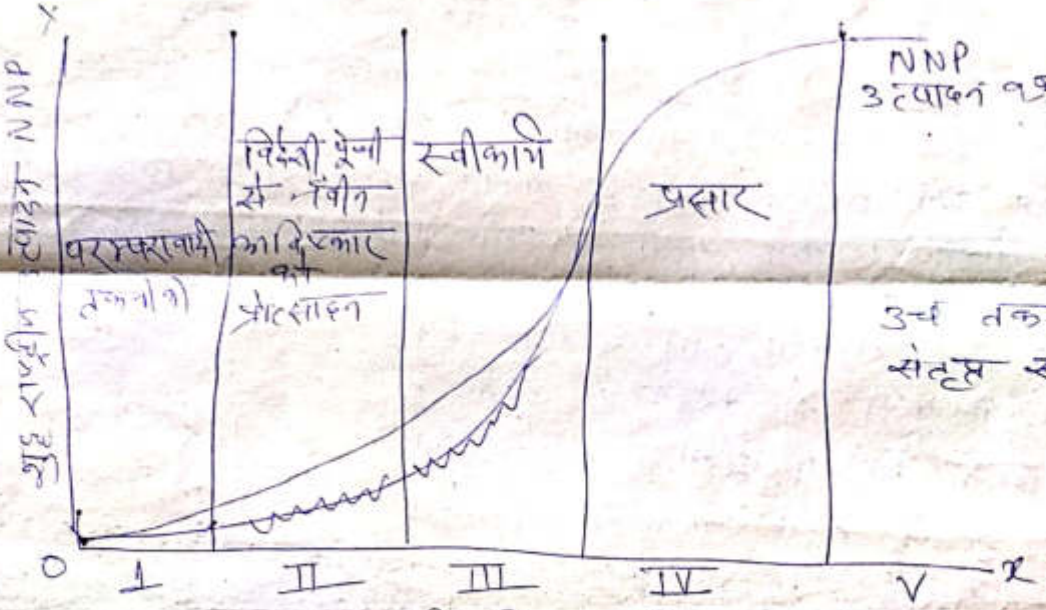

इसप्रकार विदेशी पूंजी के द्वारा नवीन आविष्कार की गति को तीव्र किया जा सकता है। जिससे विनियोग बढ़ेगा और आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी।

(4) परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु — विदेशी पूंजी द्वारा कुछ ऐसी परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है जिसका बाद में उपयोग देशी लोगों द्वारा होता है। जैसे कि भारत में रेल उद्योग का विकास विदेशी पूंजी से संभव हो सका। इसीतरह राजमार्गों, लोहा तथा इस्पात उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास विदेशी पूंजी से ही संभव है।

(5) औद्योगिक विकास हेतु — औद्योगिक विकास हेतु भी पूंजी की आवश्यकता होती है जो कि निर्यात से संभव हो चूंकि हमारे देश के द्वारा निर्यातित वस्तुओं की मांग बेलोचदार है अतः इसके लिए हमें विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है।

(6) आयोजन हेतु — आर्थिक विकास के लिए जितना आवश्यक आर्थिक आयोजन है उतना ही आयोजन को पूरा करने हेतु पूंजी। इसलिए देशी पूंजी की अपर्याप्त मात्रा को दूर करने के लिए विदेशी पूंजी को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।

Scanned with CamScanner

(7) स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ाने हेतु - विदेशी पूंजी प्रतियोगिता को बढ़ावा देती है। देशी उद्यमियों को विदेशी उद्यमियों से प्रतियोगिता करने के लिए उन्हें अपनी कुशलता को बढ़ाना पड़ता है।

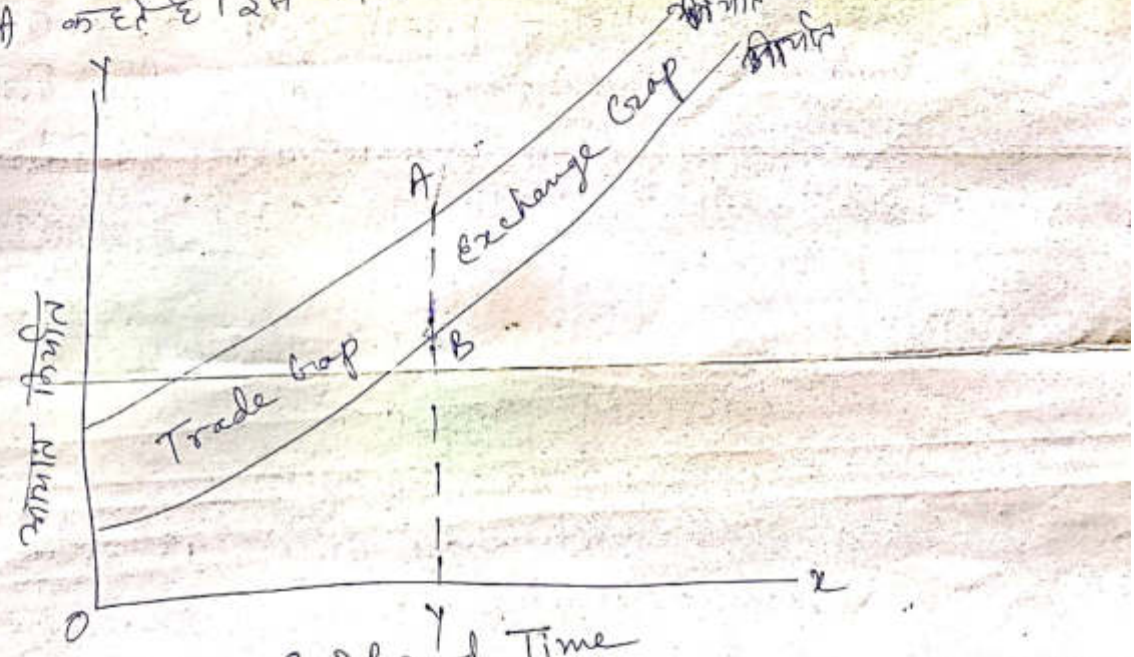

अतः विदेशी पूंजी आर्थिक विकास के लिए सहायक होती है। लेकिन विदेशी पूंजी किस मात्रा तथा किस दर तक लिया जाए यह तय करना भी आवश्यक होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे Trade Gap के द्वारा निर्धारित किया है जिसे विनिमय अन्तराल भी कहते हैं। इसे नीचे के चित्र से स्पष्ट किया गया है-

इस चित्र में अधिकतम निर्यात तथा न्यूनतम आयात को लिया गया है अतः भुगतान शेष को संतुलित करने के लिए ही विदेशी सहायता लेनी चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि बचत अन्तराल Saving Gap को पूरा करने के लिए बाह्य सहायता लेनी चाहिए। इसलिए विदेशी पूंजी की जरूरत अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है विदेशी पूंजी निम्नलिखित शर्तों पर लेना चाहिए —

(1) राजनीतिक प्रतिबंध नहीं हो — विदेशी पूंजी स्वीकार करते समय यह जरूरी है कि राजनीतिक प्रतिबंध नहीं हो।

(2) पूंजी निर्माण में बाधा न होना — ऐसा न हो कि

Scanned with CamScanner

विदेशी पूंजी लेकर सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो पूंजी निर्माण में बाधा हो जाएगा।

3. बाह्य वित्त प्रबन्ध के तरीके – बाह्य वित्त कई स्रोतों से प्राप्त होते है जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं –
(a) निर्यात प्रोत्साहन (b) आयात प्रतिस्थापन
(c) विदेशी सार्वजनिक ऋण (d) अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सीयों
(e) विदेशी मुद्रा में ऋण (f) विदेशों से प्राप्त अनुदान
विदेशी पूंजी लेने से पहले बाह्य वित्त के अन्य स्रोतों को उपयोग में लाना जरूरी है

4. विदेशी ऋण जाल – विदेशी ऋण की मात्रा दीर्घकालीन हो तथा उत्पादक कार्यों के लिए लिया जाए ताकि उसे ब्याज सहित लौटाना आसान हो। विदेशी ऋण जाल में देश फंस नहीं जाए इसका सदा ख्याल रखना होगा।

5. भुगतान शेष की प्रतिकूलता को नियंत्रित रखना – भुगतान संतुलन को अनुकूल नहीं रखने पर देश विदेशी ऋण जाल में फंस जाता है।

6. Economic Sanction का खतरा – विदेशी पूंजी का प्रवाह Economic Sanction के कारण घटा दिया जाता है अगर देश की विदेशी नीति विदेश की सरकार को पसंद नहीं हो। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर विदेशी पूंजी की मात्रा तथा भुगतान की अवधि का निर्धारण करना चाहिए।

इसप्रकार एक सीमा तक विदेशी पूंजी के प्रवाह को सुगम एवं तीव्र किया जाना चाहिए ताकि देश में कुल विनियोग का स्तर ऊँचा हो और गरीबी का दुश्चक्र को तोड़ा जा सके। दीर्घकाल में निर्यात वृद्धि के उपाय किये जाने चाहिए।

Scanned with CamScanner